(ख) क्या यह भी सच है कि इन क्षेत्रों में कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर है ;

(ग) क्या यह सच है कि इन क्षेत्रों में अधिकतम 2.000 मि० मी० वर्षा होती है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर उपज बहुत ही कम है ; यदि हां, तो उपज की औसत दर कितनी है ; और

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में उपज की दर में वृद्धि करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकटस्वामी) : (क) सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०) के अंतर्गत 13 राज्यों में 92 जिलों के 615 खण्डों की पहचान की है ।

(ख) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत शुष्क भूमि वाले क्षेत्रों को कवर किया जाता है तथा इन क्षेत्रों में कृषि वर्षा पोषित है तथा मुख्यतः मानसून पर निर्भर है ।

(ग) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने के प्रयोजन हेतु खण्डों की पहचान करने के लिये वर्षा तथा सिंचित क्षेत्र मूल पहलू माने जाते हैं । कार्यक्रम के अंतर्गत खण्डों की कवरेज का विद्यमान मानदण्ड निम्नलिखित है :—

वार्षिक वर्षा	वास्तविक बुआई क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र की प्रतिशतता
(1) 750 मि०मी० से कम	20 प्रतिशत से कम
(2) 750–1125 मि०मी०	15 प्रतिशत से कम
(3) 1125 मि०मी० से अधिक लेकिन 1650 मि० मी० से कम ।	10 प्रतिशत से कम

(घ) और (ङ) सिंचित क्षेत्रों तुलना में सूखाग्रस्त क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर उ कम है । इन क्षेत्रों में उत्पादन की औसत र तथा पैदा की जाने वाली महत्वपूर्ण फसलों के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में उत्पादन लक्ष्य दर निम्न प्रकार है :—

सूखाग्रस्त क्षेत्रों (वर्षा सिंचित) में पैदा की जाने वाली प्रमुख फसलें	1991-92 में उत्पादन की औसत दर (कि०ग्रा० हैक्टेयर) **	आठवीं पंचवर्षीय योजना में उत्पादन की लक्षित दर (कि०ग्रा० हेक्टेयर) 1996–97
मोटा अनाज	800	1033
दालें	596	694
तिलहन	754	939
कपास*	241	317

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जवाहर रोजगार योजना को बढ़ावा दिया जाना

***4822. **श्री सुरेश पचौरी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जवाहर रोजगार योजना को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या प्रस्ताव रखे गए हैं ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और वे किस हद तक पूरे किए गए ;

(ग) किन-किन राज्यों ने ये लक्ष्य पूरे नहीं किए थे ; और

* प्रत्येक 170 किलोग्राम की मिलियन गांठों में ।

** संभावित उपलब्धि ।

*** पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 3583, 10 अगस्त, 1992 से स्थानांतरित ।

(घ) किन-किन राज्यों के बारे में ये शिकायतें मिली हैं कि उन्होंने जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत आवंटित की गई निधियों का प्रयोग अन्य प्रयोजनों के लिए किया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकटस्वामी) : (क) जवाहर रोजगार योजना ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार और अल्परोजगार वाले व्यक्तियों पुरूषों और महिलाओं दोनों के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगार जुटाने के मुख्य उद्देश्य के साथ आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी कार्यान्वित की जाती रहेगी । आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यक्रम के लक्ष्यों को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक संशोधन तैयार किए जा रहे हैं ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत रोजगार सृजन हेतु निर्धारित किए गए लक्ष्य और प्राप्त उपलब्धियां निम्नोक्त प्रकार हैं :—

वर्ष रोजगार सृजन (लाख श्रम दिनों में)

	लक्ष्य	उपलब्धियां
1989–90	8757.25	8643.87
1990–91	9291.04	8745.59
1991–92	7354.34	8126.20

(ग) इन तीन वर्षों में से किसी भी वर्ष के दौरान अरूणोचल प्रदेश, गोवा जम्मू व कश्मीर कर्नाटक, मेघालय और पश्चिमी बंगाल ने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया था ।

(घ) किसी भी राज्य ने जवाहर रोजगार योजना के लिए आवंटित निधियों का अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग नहीं किया है ।

Intension sanitation project in Assam

4823. SHRIMATI BASANTI SARMA: Will tne PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have received any proposal regarding "Intensive Sanitation Project" in Kamrup district of Assam; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DAVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) Yes, Madam.

(b) State Government of Assam had sent a proposal for Intensive Sanitation Project in Kamrup district at an estimated cost of Rs. 30.13 crore. The Central Government has accorded technical approval for implementation of the scheme in principle. Phase I of the scheme to be implemented in two years has been approved at an estimated cost of Rs. 441.31 lakhs. This involves construction of 21,000 household sanitary toilets and 63,000 other sanitary facilities at a total cost of Rs. 411.57 lakhs to be shared as follows:—

(Rs in lakhs)

—Assistance from United Nations Children Fund	30.40
—Central Government	30.40
—Government of Assam	30.48
—Beneficiary contribution	320.29
TOTAL :	411.57

THEUNICEF will also contribute a sum of Rs. 29.74 lakhs towards advocacy, training, administration and establishment charges.